■ संपादकीय

# विपक्ष की मुहिम

कांग्रेस और देश भर की विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों ने सोमवार को राजधानी में आयोजित अपनी बैठक में संदेश दिया है कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पार्टियों की इस एकजुटता को अपना सियासी वजूद बचाए रखने की जद्दोजहद के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे धुंधले तरीके से एक विचार भी आकार ले रहा है। पहली बार देश में गैर-बीजेपीवाद की अवधारणा जोर पकड़ रही है। एक समय जिस तरह देश में गैर-कांग्रेसवाद का जोर दिखता था, उसी तरह अब गैर-बीजेपीवाद का खाका गढ़ा जा रहा है। दिलचस्प बात यह कि कई ऐसे दल, जो पहले गैर-कांग्रेसवादी राजनीति का हिस्सा थे, वही अब गैर-बीजेपीवादी राजनीति में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अलबत्ता तब और अब में एक बड़ा अंतर यह है कि गैर-कांग्रेसवाद एक सिद्धांत आधारित रणनीति हुआ करता था। लोहिया से लेकर जेपी और वीपी सिंह तक उसने कांग्रेसी नीतियों के बरक्स अपना एक वैकल्पिक कार्यक्रम देश के सामने पेश किया था। लेकिन गैर-बीजेपी गोलबंदी वाले दल ऐसा कोई अजेंडा लेकर सामने नहीं आए हैं। इनका ध्यान सिर्फ बीजेपी सरकार की विफलता को भुनाने पर है। कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से राफेल और कर्ज घोटालों का मुद्दा उठाकर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार को घेरा है और किसानों की उपेक्षा तथा देश में बढ़ती अराजकता के लिए सरकार की तीखी आलोचना की है। लेकिन बाकी दलों ने तो यह तकलीफ भी नहीं उठाई है। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों की सरकारें आज विभिन्न राज्यों में हैं। वहां इन दलों का रवैया सत्तारूढ़ दल से ज्यादा अलग नहीं दिखता। इन्होंने भी सत्ता में आने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप देने जैसे लोकलुभावन वादे किए हैं। विपक्ष शासित कोई भी राज्य प्रशासनिक सुधार या कानून-व्यवस्था के स्तर पर कोई अलग मानक नहीं स्थापित कर पाया है, जिसे अच्छा मानकर लोग विपक्ष के साथ खड़े हो सकें। विपक्ष का एक कमजोर पहलू यह भी है कि उसके पास कोई करिश्माई चेहरा नहीं है, जिसे जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देख सके।

# कोर्ट की सख्ती के बाद बाल संरक्षण नीति

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में लड़कियों का बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बीच इन आश्रय गृहों की स्थिति के प्रति केन्द्र सरकार भी सक्रिय हो गयी है। केन्द्र सरकार इन आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों के संरक्षण के लिये एक नीति तैयार कर रही है। सरकार ने बाल संरक्षण नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। बाल संरक्षण नीति का मकसद आश्रय गृहों और बाल गृहों के संचालन के लिये राज्यों और इनका संचालन करने वालों को दिशा निर्देश देना है ताकि इन संस्थानों में नाबालिगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

**अनूप भटनागर**

यही नहीं, इस मसौदे में बाल गृहों और बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के रखरखाव तथा इनमें बच्चों की सुख-सुविधाओं के बारे में भी दिशा निर्देश तैयार किये जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सामाजिक आडिट के दौरान एकत्र किये गये आंकड़ों का विशेषज्ञों की सहायता से विश्लेषण किया जा रहा है ताकि इन संस्थानों की खामियों को दूर किया जा सके। इन आश्रय गृहों में चल रही गड़बड़ियों का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट से हुआ, जिसने इस संबंध में बिहार सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट में कई तरह की अनियमितताओं का खुलासा हुआ था।

यह विडंबना ही है कि इन बच्चों, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, के यौन शोषण की घटनाएं सामने आने पर पुलिस भी इनकी पूरी शिद्दत से जांच नहीं करती। इसी वजह से उच्चतम न्यायालय को बिहार में 11 अन्य आश्रय गृहों की जांच का काम राज्य सरकार के तमाम विरोधों के बावजूद केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना पड़ा। मुजफ्फरपुर कांड के बाद इस साल अगस्त में उच्चतम न्यायालय ने देश के करीब तीन हजार आश्रय गृहों के सोशल आडिट के आंकड़े पेश करने का निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया था। इससे पहले, केन्द्र का कहना था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इनका सर्वे कराया था और अब इसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में देश के सभी अनाथालयों, बाल गृहों और आश्रय गृह जैसी संस्थाओं की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निगरानी में निरीक्षण कराने का निर्देश दिया था। आयोग ने अगस्त में न्यायालय को सूचित किया था कि उसने 2874 बाल गृहों का निरीक्षण किया और इनमें से सिर्फ 54 संस्थानों का कामकाज ही पूरी तरह संतोषजनक मिला। इसके बावजूद, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम सरीखे कुछ राज्यों में यह काम नहीं हो सका है। कुछ राज्यों की आनाकानी से यही संकेत मिलता है कि इनमें सब कुछ ठीक नहीं है। राज्यों की आनाकानी पर न्यायालय ने कहा भी था कि उनके इस आचरण से यही लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में बच्चों की देखभाल करने वाले 7189 आश्रय गृह हैं। इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। हालांकि इनमें से सिर्फ 5850 आश्रय गृह ही पंजीकृत हैं और 1339 ऐसी संस्थाओं का अभी पंजीकरण होना है। इनमें करीब दो लाख 33 हजार बच्चे रहते हैं। इस समय जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के आश्रय गृह लड़कियों का कथित रूप से यौन उत्पीड़न के इस्तेमाल की वजह से चर्चा में हैं तो दूसरे राज्यों में गैरकानूनी तरीके से बच्चों को गोद देने या उन्हें बेचने जैसे आरोपों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं।

अभी बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि हाल ही में दिल्ली में भी एक आश्रय गृह से नौ लड़कियों के लापता होने की घटना सामने आ गयी। न्यायालय के सख्त रुख के बाद हालांकि केन्द्र सरकार बाल संरक्षण नीति तैयार कर रही है लेकिन इस नीति के साथ ही इन बाल गृहों के प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करने के साथ ही पुलिस को अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है क्योंकि बिहार के कुछ आश्रय गृहों में अप्राकृतिक यौनाचार के मामले सामने आने पर राज्य पुलिस ने भादसं की धारा 377 की बजाय मामूली चोट लगने का मामला दर्ज किया। यह तथ्य जब न्यायालय के सामने आया तो बिहार सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं था।

राज्य सरकार को जब यह एहसास हुआ कि न्यायालय इन मामलों को सीबीआई को सौंपने जा रहा है तो उसने गलती सुधारने का मौका देने का अनुरोध किया लेकिन न्यायाधीशों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उम्मीद है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंकड़ों का यथाशीघ्र विश्लेषण करके बाल संरक्षण नीति को अंतिम रूप देगा ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सके।

# ईमानदार नहीं सरकार गंगा की परिपूर्णता पर

**भरत झुनझुनवाला**

केन्द्र सरकार ने हाल में एक विज्ञप्ति में गंगा की परिपूर्णता को पुनः स्थापित करने के प्रति अपना संकल्प जताया है। सरकार के इस मंतव्य का स्वागत है। गंगा के अस्तित्व पर इस समय जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के संकट हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत गंगा के पाट में एक किनारे से दूसरे किनारे तक बैराज या डैम बना दिया जाता है और नदी का पूरा पानी इन बैराज के पीछे रुक जाता है। बैराज के नीचे नदी सूख जाती है। गंगा अपने साथ हिमालय से जो आध्यात्मिक शक्तियां लाती हैं, जो गंगा में मछलियां नीचे से ऊपर जाती हैं और जो गाद ऊपर से नीचे आती है, यह सब बैराजों के पीछे रुक जाता है। पूर्व यूपीए सरकार ने गंगा को पुनर्जीवित करने के लिये सात आईआईटी के समूह को गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाने का कार्य दिया था। इस कार्य में देरी होने के चलते यूपीए सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव बी. के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने संस्तुति दी कि गंगा पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं से 20 से 30 प्रतिशत पानी लगातार छोड़ा जाना चाहिये। कमेटी ने स्पष्ट लिखा था कि उनकी यह संस्तुति केवल उस अंतरिम समय तक के लिये है जब तक आईआईटी के समूह द्वारा अन्तिम संस्तुतियां नहीं दी जातीं। वर्तमान एनडीए सरकार ने चतुर्वेदी कमेटी की इस संस्तुति को लागू कर दिया है। केरल सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कहा गया है कि पर्यावरण मंत्रालय नई जलविद्युत परियोजनाओं से 20 से 30 प्रतिशत पानी छोड़ने को कह रहा है।

इसके बाद आईआईटी समूह की रपट प्रस्तुत हुई। आईआईटी समूह ने संस्तुति दी कि लगभग 50 प्रतिशत पानी गंगा की परिपूर्णता बनाये रखने के लिये छोड़ा जाना चाहिये। लेकिन वर्तमान एनडीए सरकार को यह संस्तुति नहीं पसंद आयी। इसलिये उन्होंने एक दूसरी कमेटी बनाई। इस कमेटी ने आईआईटी समूह की 50 प्रतिशत की संस्तुति को घटाकर बी. के. चतुर्वेदी की 20 से 30 प्रतिशत की संस्तुति पर अपनी मोहर लगा दी। इस दूसरी कमेटी में आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर सदस्य थे जो कि आईआईटी समूह में भी भागीदार थे। इन्होंने अपने ही द्वारा दी गई संस्तुतियों को सरकार के इशारे पर घटा दिया। सरकार की सदा यह रणनीति रहती है कि एक कमेटी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी कमेटी बनाते जाओ जब तक कोई कमेटी सरकार की इच्छानुसार संस्तुति न दे। इस समय गंगा और उसकी सहायक नदियों पर चार जल विद्युत परियोजनायें बन रही हैं–फाटा, सिंगोली, विष्णुगाड एवं तपोवन। वर्तमान विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन परियोजनाओं द्वारा भी 20 से 30 प्रतिशत पानी पर्यावरणीय प्रवाह के लिये छोड़ा जायेगा। वास्तव में डैम बनाकर उससे पानी छोड़ने से नदी की परिपूर्णता स्थापित नहीं होती। बैराज के पीछे पानी के ठहरे रहने से पानी में निहित आध्यात्मिक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मछलियां नीचे से ऊपर नहीं जा पाती हैं। ये मछलियां ही पानी को साफ रखती हैं। ऊपर से आने वाली गंगा की गाद में तांबा, थोरियम तथा अन्य लाभप्रद धातुएं पायी जाती हैं। इस गाद के डैम के पीछे रुक जाने से नीचे के पानी में ये तत्व समावेश नहीं करते। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पूना ने एक अध्ययन में बताया है कि डैमों का आकार इस प्रकार बनाया जा सकता है कि उसमें बीच का एक हिस्सा खुला रहे, जिससे पानी के बहाव की निरन्तरता बनी रहे तथा मछली और गाद का आवागमन हो सके।

## खेल

# हरमनप्रीत, मंधाना को 'नीचा दिखाया' जाते हुए नहीं देख सकता: रमेश पोवार

**मुंबई।** भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच रमेश पोवार का कहना है कि वह दोबारा इस पद के लिए आवेदन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वह अपना समर्थन करने वाली सीनियर खिलाड़ियों को 'अपमानित' (नीचा दिखाया) होते नहीं देख सकते। पोवार के मुताबिक टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कोच के तौर पर उनका समर्थन इसलिए किया, क्योंकि वह जानती हैं कि इस टीम को मौजूदा मुकाम तक ले जाने के लिए तीन महीनों तक किस कदर मेहनत की गई थी।

महिला टीम के कोच पद के लिए पोवार ने फिर से आवेदन किया है और इसके लि ऐड-हॉक कमिटी के सामने इंटरव्यू 20 दिसंबर को होने हैं। पोवार का कार्यकाल 30 नवम्बर को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने उनके करार को बढ़ाने में रुचि न दिखाते हुए नए कोच के लिए विज्ञापन जारी कर दिए। इसी के तहत अन्य उम्मीदवारों के साथ पोवार ने भी आवेदन दिया है।

महिला टीम के कोच की नियुक्ति के लिए बीसीसीआई द्वारा एड-हॉक समिटी के गठन की घोषणा मंगलवार को की गई थी और इस पर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासकों का समिति (सीओए) की सदस्य डायना इडुल्जी समिति के निर्माण के खिलाफ हैं और पोवार को ही कोच पद पर देखना चाहती हैं लेकिन सीओए के प्रमुख विनोद राय ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, हरमनप्रीत और मंधाना ने बीसीसीआई द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी और सीओए को ई-मेल के जरिए पोवार को कोच पद पर बनाए रखने की अपील की थी।

ऐसे में कोच पद के लिए फिर से आवेदन करने के बारे में पोवार ने कहा, 'मैं हरमनप्रीत और मंधाना का सम्मान करता हूं। इन दोनों खिलाड़ियों ने मेरा समर्थन किया है। वे जानती हैं कि हमने इस टीम को नई ऊंचाई देने के लिए कितनी मेहनत की है। अब जो भी होगा, वह मेरे नियंत्रण में नहीं है। उनका समर्थन मुझे इस बात की संतुष्टि देता है कि मैंने जो कड़ी मेहतन की, वे उसका सम्मान करती हैं।' पोवार ने कहा, 'हमने इस कड़ी मेहनत के दम पर आठ साल बाद टी-20 विश्व कप के लिए क्वॉलिफाई किया। कोच पद के विवाद पर मैंने काफी सोच-विचार और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ चर्चा कर यह फैसला लिया है कि मुझे वह करना चाहिए, जो मेरे नियंत्रण में है। खिलाड़ियों के समर्थन का सम्मान करते हुए मुझे फिर से आवेदन देना चाहिए।'

## 37 के हुए फाइटर युवराज, ली यह शपथ

**नई दिल्ली।** युवराज सिंह भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हों लेकिन अपने फैंस के दिलों पर वह हमेशा राज करते हैं। उन्होंने रास्ते में आने वाली हर बाधा पर जीत हासिल की है। आज उनका 37वां जन्मदिन है। विश्व कप 2011 हो या वर्ल्ड टी20 2007, युवराज ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभायी। वर्ल्ड कप 2011 में तो वह प्लेयर ऑफ द टूर्नमेंट भी रहा। भारत के लिए 304 वनडे, 58 टी20 और 40 टेस्ट मैच खेलने वाले युवराज का अंतरराष्ट्रीय मंच पर धमाकेदार आगाज हुआ था।

चैंपियंस ट्रोफी के इस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। यहीं लोगों को आगाज हो गया था कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज औरों से कुछ अलग है और इसमें कुछ खास है। हालांकि वनडे में 8701 और टी20 इंटरनैशनल में 1177 रन बनाने वाले युवराज टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा नहीं बन पाए लेकिन उनकी मैच विनिंग काबिलियत हमेशा टीम के काम आती रही।

# भारतीय हॉकी टीम के सामने नॉकआउट में 'आक्रामक' डच चुनौती

**भुवनेश्वर।** विश्व कप में 43 साल बाद पदक जीतने का सपना लेकर उतरी भारतीय हॉकी टीम के सामने गुरुवार को क्वॉर्टर फाइनल में नीदरलैंड के रूप में कड़ी चुनौती होगी जो पिछले दो मैचों में दस गोल करके अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर चुका है।

विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड से एक पायदान नीचे पांचवें स्थान पर काबिज भारत ने पूल सी में तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के बाद शीर्ष पर रहकर अंतिम आठ में जगह बनाई। वहीं नीदरलैंड पूल डी में दूसरे स्थान पर रहकर क्रॉसओवर खेला और कनाडा को पांच गोल से रौंदकर क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचा।

खचाखच भरे रहने वाले कलिंगा स्टेडियम में दर्शकों को इंतजार भारत की एक और शानदार जीत के साथ पदक के करीब पहुंचने का है। आखिरी लीग मैच आठ दिसंबर को खेलने वाली भारतीय टीम चार दिन के ब्रेक के बाद उतरेगी। कोच हरेंद्र सिंह के मुताबिक असली टूर्नमेंट की शुरुआत नॉकआउट से होगी और उनकी टीम डच चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था, 'हम आक्रामक हॉकी खेल रहे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमें बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलने का अनुभव है और नीदरलैंड को भी हम हरा सकते हैं। यह टीम बड़ी टीमों के रसूख से खौफ खाने वालों में से नहीं है और मुझे यकीन है कि हम इस बार विश्व कप से खाली हाथ नहीं लौटेंगे।' कोच के आत्मविश्वास की वजह भारतीय टीम का पूल चरण में प्रदर्शन है जिसमें दुनिया की तीसरे नंबर की टीम बेल्जियम के रहते भारत ने पहले स्थान पर रहकर नॉकआउट के लिए सीधे क्वॉलिफाइ किया। साउथ अफ्रीका को पांच गोल से हराया जबकि कनाडा को 5-1 से शिकस्त दी। बेल्जियम को आखिरी चार मिनट में गोल गंवाने के बाद 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा।

सिमरनजीत सिंह, ललित उपाध्याय, मनदीप सिंह और ओडिशा के ड्रैग फ्लिकर अमित रोहिदास समेत भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया।

# तेज गेंदबाजों को घुड़दौड़ के घोड़ों की तरह बचाने की जरूरत: भरत अरुण

**पर्थ।** भारत के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने बुधवार को कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज घुड़दौड़ के घोड़ों की तरह हैं, जिन्हें अच्छी तरह से संभालने की जरूरत है। अरुण ने वर्तमान तेज गेंदबाजी आक्रमण को देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ आक्रमण करार दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने इस साल विदेशों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गेंदबाजों ने तीन मैचों में सभी 60 विकेट लिए और इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों में 90 में से 82 विकेट हासिल किए।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए ऐडिलेड की धीमी पिच पर सभी 20 विकेट लिए। अरुण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले कहा, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने (गेंदबाजों ने) केवल ऐडिलेड में ही ऐसा प्रदर्शन नहीं किया बल्कि वे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में भी ऐसा कर चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया है। यह संभवतः भारत का अब तक का तेज गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ आक्रमण है। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और इशांत शर्मा की गेंदबाजी में सुधार हुआ है क्योंकि उन्होंने निरंतरता हासिल की है।

अरुण ने कहा, निरंतरता (पिछले दौरों में) मसला होता था और हमने गेंदबाजों के मामले में इसका समाधान निकाला। इस पर वास्तव में हमने कड़ी मेहनत की। यहां तक कि अभ्यास के दौरान भी हम एक गेंदबाज की फॉर्म पर जोर देते हैं और गेंदबाजों ने बहुत अच्छी तरह से इसे आत्मसात किया। अब उसका सकारात्मक परिणाम हमें मिल रहा है। भारत के गेंदबाजी कोच ने कहा, यह बहुत सरल है।

# भारतीय कप्तानों में भी शिखर पर पहुंचने के करीब हैं कोहली

**नई दिल्ली।** विराट कोहली को भारत का सबसे सफल कप्तान बनने के लिए केवल तीन जीत की दरकार है और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्तमान सीरीज में टीम क्लीन स्वीप करने में सफल रहती है तो वह महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कप्तानी में भी शिखर पर पहुंच जाएंगे।

विश्व के नंबर एक बल्लेबाज कोहली की अगुवाई में भारत ने अब तक 43 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से 25 में उसने जीत दर्ज की है। बाकी मैचों में से नौ में भारत को हार मिली जबकि इतने ही मैच ड्रॉ छूटे। अभी धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान हैं जिनके नाम पर 60 मैचों में 27 जीत दर्ज हैं। मतलब कोहली को उनकी बराबरी करने के लिए अब केवल दो जीत की दरकार है।

ऐडिलेड टेस्ट जीतकर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की सीरीज का शानदार आगाज किया है और ऐसे में उसके पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सीरीज जीतने की संभावना भी बढ़ गई है। कोहली सबसे सफल भारतीय कप्तान बनने से पहले विदेशों में सबसे अधिक मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान बन सकते हैं। अभी यह रेकॉर्ड सौरभ गांगुली के नाम पर है जिनके नेतृत्व में भारत ने विदेशी धरती पर सर्वाधिक 11 टेस्ट मैच जीते हैं जबकि कोहली 10 टेस्ट मैचों में जीत के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। कोहली की कप्तानी में भारत ने श्री लंका में सर्वाधिक पांच जबकि वेस्ट इंडीज में दो मैच जीते। इसके अलावा उनकी अगुआई में टीम ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक-एक मैच में जीत हासिल की।

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर मैच जीतने वाले वह पांचवें भारतीय कप्तान हैं। बिशन सिंह बेदी की अगुआई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में दो मैच जीते हैं और कोहली यह रेकॉर्ड भी अपने नाम पर करना चाहेंगे। सुनील गावसकर, गांगुली और अनिल कुंबले की कप्तानी में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया में एक-एक मैच जीता है।

कोहली अगर ऑस्ट्रेलिया में सबसे सफल भारतीय कप्तान नहीं बन पाते हैं तब भी 2019 में वह यह रेकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। भविष्य के दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के अनुसार भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद 2019 में कुल आठ टेस्ट मैच खेलने हैं। एफटीपी के अनुसार भारत को मार्च में जिम्बाब्वे से एक टेस्ट खेलना है और फिर इंग्लैंड में जून में होने वाले विश्व कप के बाद जुलाई में दो टेस्ट मैचों के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत की पहली सीरीज भी होगी। भारत अगले साल अक्टूबर-नवंबर में साउथ अफ्रीका की तीन और बांग्लादेश की दो टेस्ट मैचों के लिए मेजबानी करेगा। कोहली को हालांकि विश्व का सबसे सफल कप्तान बनने के लिए अभी लंबी राह तय करनी होगी। यह रेकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका ग्रीम स्मिथ के नाम पर है जिन्होंने 109 टेस्ट में से 53 मैचों में जीत दर्ज की।

# खिलाड़ियों पर नहीं चिल्लाया गया: हॉकी इंडिया की सफाई

**भुवनेश्वर।** हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के क्वॉर्टर फाइनल मैच से एक दिन पहले एक बड़ा विवाद टल गया। हमारे सहयोगी टाइम्सऑफइंडिया डॉट कॉम ने सबसे पहले खबर दी थी कि कलिंगा स्टेडियम के वीआईपी लॉन्ज में भारतीय खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ साइन करते और सेल्फी लेते नजर आने के बाद हॉकी इंडिया के कुछ खिलाड़ी चिल्ला रहे थे।

हॉकी इंडिया ने साफ किया कि खिलाड़ियों को वीआईपी लॉन्ज में लाने वाले व्यक्ति पर चिल्लाया जा रहा था क्योंकि वहां खिलाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होती। यह नियमों की अवहेलना है और इसमें खिलाड़ी को सस्पेंड तक किया जा सकता है। हॉकी इंडिया के मुताबिक, पूरे टूर्नमेंट के दौरान कभी भी खिलाड़ियों पर नहीं चिल्लाया गया। खिलाड़ियों को हालांकि इस बात की जानकारी है कि उन्हें इन क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं है। कोच और एफआईएच द्वारा दो बार इस बारे में चेतावनी भी दी जा चुकी है।

यह घटना मंगलवार को हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और कनाडा के बीच खेले गए क्रॉस ओवर मुकाबले के दौरान हुई। इस मैच में नीदरलैंड्स ने कनाडा को 5-0 से हराया।